Security Arrangements at Airports

1707. SHRI BASANT SINGH KHALSA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether security arrangements at all the airports in the country have been tightened recently; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

(b) Airport/Aerodrom authorities have been instructed to take fool-proof measures to:—

(i) rigorously enforce all anti-hijacking and anti-sabotage checks;

(ii) make through arrangements for searching baggage and frisking passengers by responsible officers;

(iii) exercise effective surveillance over potential hijackers and maintain adequate vigilance all round;

(iv) ensure perfect physical security of airport complex; and

(v) alert airport security units and strengthen existing security measures to the extent necessary.

Suggestion for earmarking part of Excise Duty Income for investment by Industries

1708. SHRI DHIRENDRA NATH BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received suggestions from the industries urging the Ministry to earmark a part of its excise duty income for investment by industries; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) and (b). A few pre-Budget representations have been received suggesting that to encourage investment and to increase production and employment, a portion of the excise duty should be earmarked for re-investment as interest-free loan for modernisation and rehabilitation as well as expansion of industries which bear a high burden of indirect taxes.

चुंगी शुल्क

1709. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुंगी शुल्क समाप्त करने के सम्बन्ध में 2 अगस्त, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2405 के उत्तर में यह बताया था कि उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव था जिनमें चुंगी शुल्क समाप्त नहीं किया गया है और क्या बातचीत हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) अन्य राज्यों द्वारा चुंगी समाप्त न किए जाने और मध्य प्रदेश द्वारा समाप्त किए जाने से उत्पन्न विषमता को दूर करने और एकरूपता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीसतीश अग्रवाल) (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के इस आशय की घोषणा पिछले वर्ष के बजट भाषण में की गई थी कि वे राज्य सरकारें जो चुंगीकर लगाती हैं इसे हटाने के लिए उपयुक्त विधान पेश करें। सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों को, चुंगीकर समाप्त करने तथा राजस्व के वैकल्पिक स्रोतों के पता लगाने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए लिखा गया था। चुंगीकर समाप्त करने के संबन्ध में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचारविमर्श किया गया था। इस विचार-विमर्श के आधार पर इस मामले पर योजना आयोग तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से परामर्श करके आगे कार्यवाही की जा रही है।